आकाशवाणी शिमला

17.02.2026 / प्रादेशिक समाचार / 19:45बजे

मुख्य समाचार

- मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा– गग्गल एयरपोर्ट और गगरेट मे ज़मीन के बेनामी सौदों की जांच करवाएगी सरकार।
- विधानसभा में आरडीजी के मुद्दे पर सत्ता पक्ष व विपक्ष में तीखी नोकझोंक।
- उपमुख्यमंत्री ने कहा–आरडीजी हिमाचल का संवैधानिक अधिकार– नेता प्रतिपक्ष का आरोप– आरडीजी पर राजनीति कर रही सरकार।
- प्रदेश पैंशनर संयुक्त संघर्ष समिति ने अपनी लंबित मांगो को लेकर शिमला में किया धरना–प्रदर्शन– सरकार पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप।
- उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा– वर्ष 2026–27 के केंद्रीय बजट में सरकार ने इन्फ्रास्ट्रक्चर की मज़बूती पर दिया विशेष बल।

प्रश्नकाल

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश सरकार गग्गल एयरपोर्ट और गगरेट में ज़मीन के बेनामी सौदों की जांच करवाएगी। उन्होंने इसके लिए पुलिस की एस.आई.टी के गठन की घोषणा की। शिमला में चल रहे प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन आज प्रश्नकाल के दौरान उन्होंने गगरेट के विधायक राकेश कालिया द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में ये बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन दोनों स्थानों पर हुई ज़मीन की बेनामी खरीद और उसमें कथित दलाली दिए जाने के मामले की जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर किसी ने पैसे का बेनामी लेन–देन किया है, तो उसकी ज़मीन ज़ब्त होगी और उसे मुआवजा भी नहीं दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि जांच में ऐसा कोइ मामला सामने आता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इससे पूर्व मूल प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि कांगड़ा के गग्गल एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण के तहत अभी तक 4 हज़ार 6 सौ 49 लोगों को एक हज़ार 4 सौ 60 करोड़ रूपये से अधिक की राशि वितरित की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि ये राशि भू–अधिग्रहण अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रभावितों के खाते में ट्रांसफर की गई है।

विधायक इंदद्रत लखनपाल के एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि शिमला में बिजली व टेलीकॉम की तारों और पानी की पाइपों के लिए बन रही डक्ट पूरी तरह सुरक्षित है और इससे शहर को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा।

आरडीजी चर्चा

विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन आज भी राजस्व घाटा अनुदान आरडीजी पर प्रस्तुत सरकारी संकल्प पर सदन में चर्चा जारी रही। चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष व विपक्ष ने एक–दूसरे को घेरने का प्रयास किया और वित्तीय कुप्रबंधन के आरोप लगाए। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे विशेष संवाददाता.....

डिस्पैच–शिमला में चल रहे प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन राजस्व घाटा अनुदान आडीजी के मुद्दे पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष व विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। चर्चा में भाग लेते हुए उप–मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने विपक्ष को इस मुद्दे पर घेरा और पूछा कि वे आरडीजी बंद होने के पक्ष में हैं या विरोध में। उन्होंने कहा कि प्रदेश को आरडीजी मिले, ये संविधान में अधिकार दिया गया है और आरडीजी मिलना हिमाचल का अधिकार है।

दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि आरडीजी के मुद्दे पर सरकार अपना पक्ष नहीं बता रही है, केवल राजनीतिक लाभ के लिए संकल्प लेकर आई है। उन्होंने कहा कि आरडीजी के मुद्दे को लेकर भाजपा अपने स्तर पर केंद्र सरकार के समक्ष मुद्दा उठा रही है। उन्होंने कहा कि उप–मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री संविधान की व्याख्या अपनी सुविधा अनुसार कर रहे हैं।

चर्चा में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह, तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी, विधायक विक्रम ठाकुर, विनोद कुमार, भवानी सिंह पठानिया, प्रकाश राणा और हंसराज ने भी हिस्सा लिया।

रितेश कपूर आकाशवाणी समाचार शिमला।

प्रदर्शन

प्रदेश पैंशनर संयुक्त संघर्ष समिति ने अपनी लंबित मांगों को लेकर आज शिमला के चौड़ा मैदान में धरना–प्रदर्शन किया। समिति के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश ठाकुर ने बताया कि सरकार द्वारा पैंशनरों की मांगों को बार–बार अनेदखा किया जा रहा है। उन्होंने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार पैंशनरों और कर्मचारियों की विरोधी बन गई है। सुरेश ठाकुर ने कहा कि राजस्व अनुदान घाटे के बंद होने का पैंशनरों की पैंशन और कर्मचारियों के वेतन व बकाया राशि से कोई लेना–देना नहीं है। पैंशनर संयुक्त संघर्ष समिति ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप भी लगाया।

नरेश बंसल

उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद डॉक्टर नरेश बंसल ने कहा है कि वित्त वर्ष 2026–27 के केंद्रीय बजट में सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया है। धर्मशाला में आज एक पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि बजट में रेलवे, विमानन और जल परिवहन में बड़े प्रावधान किए गए हैं ताकि कनेक्टिविटी बढ़े और आर्थिक विकास को गति मिले। नरेश बंसल ने बजट को "शानदार और आमजन हितैषी" बताया। उन्होंने कहा कि 53 लाख करोड़ रुपये से अधिक के इस बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और महिला सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया गया है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने आर्थिक विकास और नियंत्रित महंगाई को सुनिश्चित किया है।

जुकारू उत्सव

चंबा ज़िला की पांगी घाटी में कल से जुकारू उत्सव शुरू हो रहा है। चंबा ज़िला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुरजीत शर्मा भरमौरी ने पंगवाल समुदाय को जुकारू उत्सव की शुभकामनाएं दी हैं। इस बीच स्वजागृति संस्था के प्रधान देवराज शर्मा और उप–प्रधान करताप सिंह ठाकुर ने भी पंगवाल समुदाय के सभी लोगों को जुकारू उत्सव की शुभकामनाएं दी हैं।

मुख्य समाचार एक बार फिर

- मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा– गग्गल एयरपोर्ट और गगरेट मे ज़मीन के बेनामी सौदों की जांच करवाएगी सरकार।
- विधानसभा में आरडीजी के मुद्दे पर सत्ता पक्ष व विपक्ष में तीखी नोकझोंक।
- उपमुख्यमंत्री ने कहा–आरडीजी हिमाचल का संवैधानिक अधिकार– नेता प्रतिपक्ष का आरोप– आरडीजी पर राजनीति कर रही सरकार।
- प्रदेश पैंशनर संयुक्त संघर्ष समिति ने अपनी लंबित मांगो को लेकर शिमला में किया धरना–प्रदर्शन– सरकार पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप।
- उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा– वर्ष 2026–27 के केंद्रीय बजट में सरकार ने इन्फ्रास्ट्रक्चर की मज़बूती पर दिया विशेष बल।